



पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के कुछ रोचक तथ्य - जीके नोट्स पीडीएफ!

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के प्रयास में, 'Niche' या 'Differentiated' बैंकों की एक नई श्रेणी की घोषणा की है। इस श्रेणी के तहत दो नए प्रकार के बैंकिंग सिस्टम पेश किए गए हैं, अर्थात्ः भुगतान बैंक और छोटे बैंक। आइए हम यह समझने की कोशिश करें कि भुगतान बैंक क्या हैं और कैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) अपने नागरिक डाक नेटवर्क के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के दरवाजे पर बैंकिंग सुविधा देगा जिसे 1 सितंबर को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। आईपीपीबी देश के हर नुक्कड़ और कोने तक पहुंचने का लक्ष्य रखेगा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। तो आइये जानते है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से जुड़ी कुछ रोचक बातों को। आप इसे पढ़ने के बाद पीडीऍफ़ में भी डाउनलोड कर सकते हो।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, आईपीपीबी को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के तहत विशिष्ट लाइसेंस शर्तों के साथ लाइसेंस प्राप्त होगा। भुगतान बैंक को अपने नामों में "भुगतान" का उपयोग करके अन्य बैंकों से खुद को अलग करने की आवश्यकता होगी। आईपीपीबी न केवल वित्तीय समावेश को चलाएगा और भारत के विकास में सहायता करेगा बल्कि रोजगार के अवसरों को भी बढाएगा और गरीबों को सशक्त बनाएगा।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 9 प्रमुख बातें

- आईपीपीबी में सरकार की 100% हिस्सेदारी है, जो कि डाक विभाग के तहत स्थापित है। आईपीपीबी काउंटर सेवाओं,
 माइक्रो एटीएम, मोबाइल बैंकिंग ऐप, संदेश और इंटरैक्टिव वॉयस प्रतिक्रिया जैसे उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करेगा।
- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) किसी भी अन्य बैंक की तरह होगा लेकिन इसके संचालन किसी भी क्रेडिट जोखिम के बिना छोटे पैमाने पर होंगे और यह ऋण अग्रिम नहीं कर सकता है और न ही क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है।
- आईपीपीबी सेवाएं 1 सितंबर 2018 से 650 शाखाओं और 3,250 एक्सेस पॉइंट्स पर उपलब्ध होंगी और आखिरकार दिसंबर 2018 तक सभी 1.55 लाख डाकघरों तक पहुंच जाएगी। इनमें से 1.30 लाख पहुंच बिंदु ग्रामीण इलाकों में स्थित होंगे।











- आईपीपीबी प्रत्येक व्यक्ति के दरवाजे पर बैंक और बैंकिंग सेवाओं को लेने के लिए लगभग 3 लाख पोस्टमैन और 'ग्रामीण डाक सेवकों' के डाकघरों और जनशक्ति के नेटवर्क का उपयोग करेगा।
- बैंक 1 लाख रुपये तक की जमा राशि, प्रेषण सेवाएं, मोबाइल भुगतान / स्थानान्तरण / खरीद और अन्य बैंकिंग सेवाओं
 जैसे एटीएम / डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफर की स्वीकृति स्वीकार करेगा।
- जबिक १ लाख रुपये से अधिक किसी भी खाते में जमा स्वचालित रूप से पोस्ट ऑफिस बचत खाते में परिवर्तित हो जाएगी। यह बचत खातों पर 4% ब्याज दर की पेशकश करेगा।
- आईपीपीबी खातों को खोलने के लिए आधार का उपयोग करेगा, जबिक एक क्यूआर कार्ड और बॉयोमीट्रिक्स प्रमाणीकरण, लेनदेन और भुगतान चलाएंगे। लेनदेन को संभालने के लिए ग्रामीण डाक सेवकों को स्मार्टफोन और बॉयोमीट्रिक उपकरणों के साथ सशस्त्र बनाया जाएगा।
- आईपीपीबी ने पीएनबी और बजाज एलियाज लाइफ इंश्योरेंस जैसे वित्तीय सेवा प्रदाताओं के ऋण और बीमा जैसे तीसरे पक्ष के उत्पादों के साथ भी मिलकर काम किया है। आईपीपीबी को अपने स्वयं के सेटअप के साथ लगभग 17 करोड़ डाक बचत बैंक (पीएसबी) खातों को जोड़ने की अनुमित भी है।
- हालिया अधिसूचना में मंत्रिमंडल ने एयरटेल भुगतान बैंक और पेटीएम भुगतान बैंक जैसे मौजूदा ऑपरेटरों के साथ बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आईपीपीबी पर 1,435 करोड़ रुपये खर्च करने में 80% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस भुगतान बैंकों का लॉन्च वाणिज्यिक बैंकिंग में 'एक-आकार-फिट-ऑल' दृष्टिकोण को लाएगा। एसबीआई, आरआईएल, पेटीएम, फ्यूचर ग्रुप, वोडाफोन, यस बैंक आदि जैसे संगठन भारत में भुगतान बैंक लॉन्च करने के लिए आवेदन कर चुके हैं।

आशा है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के ज्ञान ने विभिन्न सरकारी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका ज्ञान बढ़ाया है।इसके अलावा अन्य विषयों के बारे में जानें जिन्हें विभिन्न सरकारी परीक्षाओं के करंट अफेयर्स सेक्शन में पूछे जाने की उम्मीद है।

भारतीय रेगुलेटरी बॉडीज की सूची	भारत के बंदरगाह की सूची
भारत के राष्ट्रीय उद्यान की सूची	भारत के खेल स्टेडियम की सूची
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और विजेताओं की सूची	



